दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 03 अक्टूबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 08

महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना मदद के लिए दूसरी किश्त में राज्यों को भेजे गए 7,274 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने कोविड से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 23 राज्यों के राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में केंद्रीय हिस्से की 7,274.40 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला केंद्र सरकार की उस पहल के तहत किया है, इसमें राज्य सरकारों को किसी भी आपदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने की सुविधा प्रदान की गई है। पांच राज्यों को पहले ही 1599.20 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें एसडीआरएफ के तहत सहायता की मदों और मानदंडों को संशोधित किया गया था और इसके साथ कोविड-19 की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। एसडीआरएफ मानदंडों में इस संबंध में प्रावधान किया गया है ताकि उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 जून को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा 11 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया जा सके। गृह मंत्रालय के मुताबिक, राज्य सरकारों के पास वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उनके एसडीआरएफ में राज्य के हिस्से सहित 23,186.40 करोड़ रुपये की राशि होगी। यह राशि एसडीआरएफ में उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस (शुरुआती राशि) के अलावा होगी। इससे राज्यों को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने और अन्य अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने का खर्च पूरा करने में मदद मिलेगी।

चुनाव आयोग की कार्रवाई में लोजपा का चुनाव चिह्न जब्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रही तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त कर लिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि पासवान या चिराग के दो समूहों में से किसी को भी लोजपा के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने अंतरिम उपाय के रूप में दोनों से अपने समूह का नाम और प्रतीक चुनने को कहा है, जो बाद में उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी। 16 जून को चिराग पासवान की गैर-मौजूदगी में पांचों सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया था। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दी गई, अगले दिन लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी। 17वीं लोकसभा में लोजपा के कुल छह सांसद हैं, जिनमें पांच सांसदों पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने चिराग पासवान को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसके बाद उन्होंने चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया था।

ब्राजील में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत, 22 घायल

ब्रासीलिया। ब्राजील के पूर्वोत्तर राज्य बाहिया में एक बस, एक ट्रक और एक ट्रेलर की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गयी और 22 अन्य घायल हो गये। यह दुर्घटना बाहिया राज्य के दक्षिणी हिस्से में यूनापोलिस नगर पालिका में हुई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गयी और 22 लोग घायल हो गये। घायलों में से पांच की हालत गंभीर बतायी जा रही है। पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब ट्रेलर ट्रक से अलग होकर आगे वाली गली में जा घुसा। हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया।

भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में हैदराबाद के 3 लोग हुए शामिल

हैदराबाद (आरएनएस)। भारत में अरबपतियों की संख्या के मामले में तेलंगाना का देशभर में छठा स्थान है, जबकि हैदराबाद चौथे स्थान पर है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के हालिया आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। हैदराबाद के 56 व्यक्तियों और परिवारों के पास 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। पिछले एक साल के दौरान शहर ने पांच अरबपतियों को इस सूची में जोड़ा है।

राज्य में कुल 63 अरबपति हैं, जो 2020 से आठ ज्यादा हैं।

हैदराबाद के तीन व्यक्ति या परिवार ने 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में जगह बनाई है।

अमेरिका में प्रशिक्षित वैज्ञानिक और ड्रग रिसर्च फर्म हैदराबाद की दिवि लैबोरेट्रीज के संस्थापक मुरली दिवी 79,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर हैदराबादी और 14वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक

साल में उनकी संपत्ति में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल उन्हें 17वां स्थान मिला था।

बी. पार्थसारधि रेड्डी और हेटेरो लैब्स का परिवार सबसे धनी भारतीयों की सूची में 58वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल वह 81वें स्थान पर था। उनके पास 26,100 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो एक साल में 88 फीसदी बढ़ी है।

अरबिंदो फार्मा ग्रुप के पी. वी. रामप्रसाद रेड्डी की संपत्ति में छह फीसदी की गिरावट आई है। वह 33 स्थान की गिरावट के साथ 86वें स्थान पर हैं। न्यू जर्सी में रहने व्यवसायी के पास 19,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

हैदराबाद के सभी तीन अरबपति 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में फार्मा क्षेत्र से आते हैं। यह आंकड़े एक बार फिर साबित करते हैं कि हैदराबाद को देश का फार्मास्युटिकल हब क्यों कहा जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, फार्मा सेक्टर 130 प्रविष्टियों के साथ सबसे अमीर भारतीयों की सूची में सबसे अधिक योगदान देता है, जिसमें 40 अरबपति शामिल हैं। 2021 में, इस क्षेत्र में संचयी संपत्ति में 43 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि 2020 में इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दवा क्षेत्र ने इस वर्ष की सूची में 12 नाम जोड़े और इस वर्ष 3,45,900 करोड़ रुपये की संपत्ति जोड़ी।

255 व्यक्तियों के साथ मुंबई सबसे अमीर व्यक्तियों वाले भारत के शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद नई दिल्ली (167), बेंगलुरु (85) का नंबर आता है। हैदराबाद ने चौथा स्थान बरकरार रखा है, जबकि चेन्नई ने अहमदाबाद को पीछे छोड़ते हुए पांचवें स्थान पर कब्जा किया है।

देश के अमीरों की इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल टॉप पर बने हुए हैं। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दो पायदान चढ़कर देश के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार ने बदला फैसला, पंजाब और हरियाणा में कल से होगी धान की खरीद

नई दिल्ली (आरएनएस)। धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर किसानों के भारी विरोध के बाद फिर से तारीख बदलकर 3 अक्टूबर कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद कल से होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने तीन अक्टूबर से धान की खरीद की तारीख की घोषणा की। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के बाद खट्टर ने कहा, मॉनसून में देरी की वजह से केंद्र सरकार ने धान और बाजरे की खरीद को 1 अक्टूबर से टालकर 11 अक्टूबर कर दिया था। इसको जल्दी शुरू करने की मांग है। खरीद कल से ही शुरू हो जाएगी। चौबे ने भी इस बात को दोहराते हुए हुए कहा कि खरीफ फसलों की खरीद कल से ही पंजाब और हरियाणा में भी शुरू हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने धान की खरीद में हुई देरी के विरोध में शनिवार को कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस और हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के आवास तथा पंजाब में जिला आयुक्त कार्यालयों का घेराव किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोनों राज्यों के विधायकों के घरों के सामने विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान शुक्रवार को किया था। वहीं, पंजाब में किसान कई कांग्रेस विधायकों के आवासों के बाहर एकत्र हुए। धान की खरीद में हुई देरी के मुद्दे पर रूपनगर में विधानसभा अध्यक्ष राणा के पी सिंह और मोगा में विधायक हरजोत कमल के घर के बाहर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को यूपी सरकार ने बनाया ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी अति महत्वकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कांगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री ने ओडीओपी उत्पाद भेंट किया। उन्होंने बताया कि वह ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के जरिए यूपी के एक-एक जिले के उद्यम कौशल का डंका दुनिया में बजाने के लिए कई प्रयास शुरू हुए हैं।

एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रदेश सरकार ने यूपी के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गयी है। जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य है कि यूपी के हर जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा, जो उस जिले की पहचान बनेगा। यह बिजनेस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

डीएनए के लिए किसी शख्स को बाध्य करना निजता का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य करना उसके निजता के अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब तक पक्षकार खुद डीएनए टेस्ट के लिए तैयार नहीं होता है तब तक उसे इसके लिए बाध्य करना उसकी पर्सनल लिबर्टी और निजता के अधिकार में दखल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएनए टेस्ट रूटीन तौर पर करने के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सिर्फ उसी केस के लिए कहा जा सकता है जिसमें जरूरी है। साथ ही कहा कि संबंधित पार्टी के इच्छा के विपरीत यह करना उसके निजता के अधिकार और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में रिलेशनशिप के विवाद में अगर रिश्ते को साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य मौजूद हों तो फिर साधारण तौर पर कोर्ट को ब्लड टेस्ट का आदेश देने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस

आर. सुभा रेड्डी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि डीएनए टेस्ट एक यूनिक स्थिति है और इसका इस्तेमाल व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए या फिर परिवार के संबंध जानने के लिए या फिर संवेदनशील हेल्थ कंडिशन जानने के लिए होता है। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले एक आवेदन को हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिवंगत दंपत्ति द्वारा संपत्ति छोड़ी गई थी जिसके मालिकाना हक की मांग याचिकाकर्ता ने की थी। वहीं दंपत्ति की तीन बेटियों ने कहा था कि याचिकाकर्ता दंपत्ति के संतान यानी बेटा नहीं है। इसी मामले में याचिकाकर्ता के डीएनए किए जाने की मांग की गई थी और याची ने कहा था कि ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

18 महीने बाद खुला भारत-नेपाल का वीरगंज बॉर्डर

नई दिल्ली (आरएनएस)। करीब 18 माह से कोविड संक्रमण के कारण बंद नेपाल के वीरगंज बॉर्डर को भारतीय समेत तीसरे देशों के नागरिकों व भारतीय वाहनों की आवाजाही के लिए औपचारिक तौर पर खोल दिया गया। नेपाल कस्टम ने कोविड से जुड़ी शर्तों के साथ भारतीय निजी वाहनों के प्रवेश की अनुमति दे दी। इससे बॉर्डर से सटे क्षेत्र के लोगों में हर्ष है। सुबह करीब सवा दस बजे वीरगंज स्थित नेपाल कस्टम पर सबसे पहले भारतीय वाहन से पहुंचे टूर-ट्रेवल्स व्यवसायी देशबन्धु गुप्ता व मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी संगठन के एम राम, दीपक कुमार, अनुज कुमार, लव कुमार समेत अन्य को एंट्री दी गई। इसके लिए इन्हें हेल्थ डेस्क के थर्मल स्क्रीनिंग व कोविड जांच से गुजरना पड़ा। रिपोर्ट

निगेटिव आने व नेपाल इमिग्रेशन के अधिकारियों द्वारा सीसीएमसी फॉर्म भरवाने के बाद प्रवेश की अनुमति मिली।

इससे पहले वीरगंज बॉर्डर के शंकराचार्य गेट पर पर्यटन एवं होटल व्यवसायी संघ समेत नेपाल, कस्टम, इमिग्रेशन व आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस आदि के अधिकारियों ने सबसे पहले प्रवेश पाने वाले भारतीय दल का फूल माला से स्वागत किया। वीरगंज के मेयर विजय सरावगी, होटल एवं पर्यटन व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हरी पंत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचेन्द्र सिंह थापा, महासचिव माधव बस्नेत, उपाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठ, पर्यटन पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष शंकर आचार्य, राधे श्याम पटेल आदि भी मौके पर थे।

पंत व आचार्य आदि ने बॉर्डर खोलने व भारतीय वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का आभार किया। कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार की तरक्की के साथ ही द्विपक्षीय जनता के स्तर संबंधों में भी मजबूती आएगी।

बॉर्डर बंद होने के बाद रक्सौल से वीरगंज जाने के क्रम में शंकराचार्य गेट के पास बायीं तरह तार-कांटे का बैरियर लगा दिया गया था, जिसे आर्म्ड पुलिस फोर्स व नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने काट कर हटाया गया। उसके बाद पहले भारतीय वाहन को प्रवेश मिला।

हत्या के आरोप में मां, बच्चे दोनों हुए गिरफ्तार

शिवमोग्गा (आरएनएस)। कर्नाटक में पुलिस ने शिवमोग्गा जिले में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और बच्चों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने 26 सितंबर को अचापुरा गांव निवासी विनोद (45) की हत्या कर दी गई थी। लेकिन घटना दो दिन बाद ही सामने आई, जब क्षेत्र के एक जंगल में चालक की सीट पर एक शव के साथ पूरी तरह से जली हुई कार मिली।

गिरफ्तार लोगों की पहचान पीड़िता की पत्नी बीनू (42), उनके बड़े बेटे विवेक (21), छोटे बेटे विष्णु (19), बीनू की बहन के बेटे अशोक (23) और विनोद के भाई संजय (36) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार विनोद की हत्या करने के बाद आरोपी शव को हुनसेकोप्पा वन क्षेत्र में एक कार में ले गया और आत्महत्या का मामला बनाने के लिए उसमें आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि पड़ोसी शहर की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर पीड़ित ने अपने परिवार के साथ लड़ाई की। इस मुद्दे ने उनके और उनके परिवार के सभी सदस्यों के बीच संबंधों में दरार पैदा कर दी। हाल ही में विनोद ने अपनी जमीन बेच दी थी और अपने दोस्त को बड़ा हिस्सा देने की योजना बनाई थी।

दो बहनें साथ पढ़ रहीं तो एक की फीस माफ करें निजी स्कूल - मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ (आरएनएस)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेटियों को शिक्षा का अनूठा उपहार दिया। निजी स्कूलों में पढ़ने वाली एक परिवार की दो बेटियों में से एक की फीस माफ करने को कहा है। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो सम्बंधित विभाग एक छात्रा की फीस की व्यवस्था करे। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तो उनका लगभग निःशुल्क पठन-पाठन का काम हो रहा है। अब हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा पर हमने बड़ी योजना तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल में अगर एक ही घर से दो बहने पढ़ती हैं तो अभिभावक स्कूल में एक की फीस माफ करने की अपील करें। उनकी अपील पर भी अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो शिक्षा विभाग फीस भरने की व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग फीस भरने में असमर्थ हैं, इससे उनको मदद मिलेगी। केन्द्र के साथ यूपी सरकार भी किसी को किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहने देगी।

गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2020-21 के तहत 1, 51, 215 मेधावी छात्रों को 177.35 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित बड़ी संख्या में मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने योजना के 10 लाभार्थी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी दिए।

योगी ने कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 नवंबर तक पात्र सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाए। छात्रवृत्ति योजना छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में करें। कोई भी छात्र छात्रवृत्ति से महरूम न रहें। सीएम ने कहा कि साल 2012-13 में जो छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति 1800 करोड़ रुपये मिलती थी। वर्तमान में उसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने तीन हजार नौ सौ करोड़ रुपये करने का काम किया है। यह प्रदेश में हर तबके के बच्चों को शासन की ओर से दी जाने वाली बड़ी राहत है।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किये। कहा कि राष्ट्रपिता ने दुनिया के सामने अहिंसा, मैत्री और करुणा के रूप में आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। स्वदेशी, स्वावलंबन का भाव आम नागरिकों में जागृत किया। हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि गांधी जी के स्वदेशी के लक्ष्य और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आज उत्तर प्रदेश सरकार साकार कर रही है। हम गांव में रोजगार सृजन के अवसर दे रहे हैं, यही गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना था। योगी ने कहा कि आज शास्त्री जी की जयंती भी है। उन्होंने राजनीति में शुचिता की स्थापना की। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाया। 1965 के युद्ध मे उन्होंने दिखाया कि भारत भी दुश्मनों को मुहतोड़ जवाब दे सकता है।